

## राष्ट्रदूत

कोटा  
Rashtradoot

कोटा, मंगलवार 8 सितम्बर, 2026



भाजपा सरकार की नीति और नीयत से बदली राजस्थान की किस्मत

नगर निकाय चुनाव में  
**कमल** खिलाना है  
विकास को आगे बढ़ाना है

प्रिय प्रदेशवासियों,

हमारी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर शहर आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ, सुरक्षित, सुगम और नागरिक-केंद्रित बने। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार ने पिछले 32 महीनों में नगरीय विकास को नई गति देने के लिए निरंतर कार्य किया है।

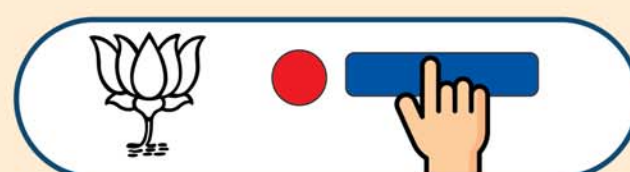
आपसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकायों में विजय दिलाकर हमारी डबल इंजन की सरकार में शहरी सरकार का तीसरा इंजन जोड़ें और ट्रिपल इंजन की सरकार का निर्माण कर विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सहयोगी बनें।

कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकायों के कुशासन से आप भली-भांति परिचित हैं। कांग्रेस के कुशासन का दौर गया, अब विकास की बारी है। कुशासन से त्रस्त थे, अब सुशासन का साथ दें।

इसलिए, घर से निकलें, बूथ तक जाएं और भाजपा के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

- मदन राठौड़

- भजनलाल शर्मा

निकाय चुनाव हेतु भाजपा का  
**संकल्प पत्र पढ़ने के लिए**  
**QR कोड स्कैन करें**भाजपा के काम पर मोहर लगाएं  
दिनांक 9 / 11 सितंबर को वोट देने जरूर जाएंकमल का बटन दबाएं  
भाजपा को जिताएं

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

## विचार विन्धु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है।—हरिभाऊ उपाध्याय

# देश का माहौल बदल रहा है

गत चार माह से देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। 10-12 सालों से लगने लगा था कि देश अधिनायकवाद और तानाशाही की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है। लोग, सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलने में डरने लगे थे। जो कोई भी साहस करके सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता, चाहे वह स्टैंड अप कॉमेडियन हो, शिक्षा विद हो, साहित्यकार हो या कलाकार ही क्यों न हो, उसकी आवाज को दबाने के लिए सरकार अपनी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ते हुइ देवी गई। आई टी, ई डी और सी सी आई इस कार्य में सबसे अग्रणी रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी छवि बन गई कि देश में स्वतंत्र मत को व्यक्त करना कठिन होता जा रहा था। यह सब लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं थे।

जब सब कुछ निराशाजनक दिखाई दे रहा था, तभी एक छोटी सी घटना ने वातावरण को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। एक केस की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 15 मई, 2026 को युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे दी। इसी को आधार बनाकर अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने 16 मई, 2026 को “कॉकरोच जनता पार्टी” का गठन कर लिया। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सप्ताह में ही दो करोड़ से अधिक फॉलोअर्स बन गए। प्रारंभ में इसे केवल सोशल मीडिया का बुलबुला माना जा रहा था। जब NEET परीक्षा के पेपर लीक होने के प्रकरण ने जोर पकड़ा तो अभिजीत दीपके, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए 6 जून 2026 को भारत आया और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस को संबोधित किया। कुछ समय देने के बाद भी जब सरकार ने प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। इसमें अधिकांश GenZ अर्थात 14 से 29 वर्ष के युवा थे। इनके समर्थन में प्रख्यात शिक्षा विद और सामाजिक कार्यकर्ता सौनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गये। यहां प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग देश के कई भागों से पहुंचने लगे। इसे कई संगठनों और राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त होने लगा।

छात्रों ने सुजनात्मकता का परिचय देते हुए कई नुक़्कड़ नाटक किए, गीत बनाए, मीम बनाए जिनमें मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी व्यंग्य किए गए। ये सोशल मीडिया पर खूब चले, हालांकि इस बारे में कोई कवरज मुख्य धारा के मीडिया (जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है) द्वारा नहीं किया गया।

मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 18 जुलाई की सुबह सौनम वांगचुक को बलपूर्वक आमरण अनशन से उठाकर अस्पताल में भरती करा दिया। उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निकालने का आह्वान किया गया था। इस दिन पुलिस ने अनशनरत छात्रों पर बहुत बल प्रयोग किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के अलावा ‘पैलेट गन’ का इस्तेमाल किया गया, हालांकि दिल्ली पुलिस इससे इनकार करती रही। राहुल गांधी एवं कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इस मुद्दे को मीडिया और संसद में जोर शोर से उठाया गया जिसके कारण संसद नहीं चल पाई। राहुल गांधी द्वारा कई घंटों तक थाने में धरना देने के बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को पैलेट गन संबंधी एफ आई आर दर्ज करनी पड़ी।

जब सरकार को आंदोलन अपने नियंत्रण से बाहर होता दिखा तो सरकार के मंत्रियों ने जे पी नड्डा के नेतृत्व में सी जे पी के नेताओं के साथ वार्ता के बाद एक समझौता 25 जुलाई 2026 को किया। इसके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी गई, आंदोलनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं करने का आश्वासन दिया गया और दर्ज सभी एफ आई आर को वापस लेने की बात की गई। साथ ही, जिन परिवारों के बच्चों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक के कारण आत्महत्या की, उनको मुआवजा देने के प्रश्न पर भी समझौता हुआ।

समझौते के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तुरंत करवा लिया गया, किंतु अन्य दो मांगों पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी एफ आई आर निरस्त करने के आदेश दिए। यह आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू किया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकांश आंदोलनकारी छात्र ‘जैन जी’ की परिभाषा में आते हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद नाम की 15 वर्षीय दलित छात्रा के पिता संजय कुमार का सिर स्वतंत्र भारद्वाज नामक व्यक्ति ने अपने कड़े के वार से फोड़ दिया था, जिससे, उसके ठंके आए। इसके बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में एफ आई आर दर्ज की और वह कई दिन तक खुला घूमता रहा और शेखी बघारता रहा। न केवल यह, इस घटना के बाद उसने एक पॉडकास्ट में इस सारी घटना को स्वीकार भी किया और कहा कि उसने ‘हाफ मर्डर’ कर दिया, फिर भी उसके विरुद्ध किसी प्रचार की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिल्ली पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि उसके निकट संपर्क केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा के अन्य बड़े-बड़े लोगों से हैं। उसका यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस प्रकरण में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्वतंत्र भारद्वाज पर एएससी एलटी एक्ट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई। युवा लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण यहां भी अंततः पुलिस को स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करना पड़ा और

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो

घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार

से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस

दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही

सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में

अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम

नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर

हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत

है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

हूए उसे गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू कर दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत किसी को जमानत भी नहीं मिल सकती है।

यह प्रकरण जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो वहां के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और अचल सचदेव की खंड पीठ ने एन एस ए की कार्यवाही को एकदम मरमाणा और अस्पष्ट मानते हुए रद्द कर दिया। यही नहीं, गलत हिरासत में रखने के लिए आकृति चौधरी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। यूपीए की यह राशि नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों के हतन से वसूल करने के आदेश दिये। यह उल्लेखनीय है कि मेधा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अतुल श्रीधरन वही न्यायाधीश थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में वहां के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश तब दिए थे जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरेशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस आदेश के तुरंत बाद इनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश से इलाहाबाद न्यायालय में कर दिया गया।

इन घटनाओं से यह तो स्पष्ट हो गया है कि नागरिकों को गुलाम या प्रजा मानने के स्थान पर, वास्तव में नागरिक समझना प्रारंभ कर दिया है। वे सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाने लगे हैं। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का काम कुछ निष्पक्ष और साहसी न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों से किया है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, यदि उनसे अपेक्षित कार्य करें, तो आम नागरिकों को अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार का विरोध करने के अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। बस, केवल कुछ साहस की जरूरत थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से लोगों में उत्पन्न होने लगा है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिलाना कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि नहीं है। किंतु एक काम को बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है, वह, यह कि कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद, पूरे देश में युवा छात्र और बच्चे तक जिन्हें ‘जैन अल्फा’ कहा गया है, स्कूल की खराब स्थिति के बारे में खुलेआम बोलने लगे हैं और आंदोलन करने लगे हैं। कई स्थानों पर इसके कारण प्रशासन पर दबाव पड़ा और उन्होंने तुरंत फुरत में जरूर स्कूलों को गिराकर उनके स्थान पर नए स्कूल या कमरे बनाने के लिए न केवल राशि स्वीकृत की, बल्कि उसका काम भी प्रारंभ करवाया। इसी संदर्भ में, पाठकों के लिए यह जानना उपयुक्त होगा कि अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त, 2026 से स्कूल टीका को अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग भागों में अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की स्थिति को देख रहे हैं और उसके बारे में वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे हैं।

राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल, जो भैंस के तबले में चल रहा था, वहां सी जे पी के आशुतोष रांका ने जाकर वीडियो बना का प्रयास किया तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इसके बावजूद प्रशासन को इसका संज्ञान लेना पड़ा और स्कूल को ठुडकाकर उसके स्थान पर नया स्कूल बनवाना प्रारंभ किया गया है। ऐसी स्थिति कई जगह सामने आई है जहां बच्चों के और युवाओं के दबाव में सरकार को स्कूलों से संबंधित काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

नागरिकों में सरकार विरोध का अनावश्यक डर निकल जाना एक बहुत बड़ी घटना है, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। कॉकरोच जनता पार्टी, एक नेतृत्व करने वाले ग्रुप के रूप में उभरी है। उन्हें केवल यह संयम बरतना होगा कि वह चुनावी राजनीति में न आए वरना उसका भी वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ।

सरकार को भी यह चाहिए कि वह विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का काम करें। वर्तमान में तो स्थिति यहां तक हो गई है कि कोई विश्वविद्यालय यदि किसी ऐसे व्यक्ति को वक्तव्य रूप में बुला ले जो सरकार की नीति की आलोचना करता हो, तो संभव है, उसकी अनुमति ही नहीं मिले और मिल जाए तो उसे भी निरस्त कर दिया जाए।

छात्रों को ताकत कितनी है, इसका एक नमूना हैदराबाद के बिधि विश्वविद्यालय NALSAR के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया, जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत से डिग्री नहीं लेंगे और कन्वोकेशन में उन्हें नहीं बुलाया जाए। छात्रों के विरोध के बाद कन्वोकेशन निरस्त कर दिया गया और उन्हें डिग्री वैसे ही दे दी गई। जब बार कार्डसिल ऑफ इंडिया ने आंदोलनकारी छात्रों का पंजीकरण, बार कार्डसिल में नहीं करने का आदेश जारी किया तो उसे दो घंटे में ही वापस लेना पड़ा।

इन सारी घटनाओं से यह लगता है कि लोगों में अपनी बात कहने की हिम्मत आई है। प और यह भी उन्हें आसन्न हो गया है कि यदि वे अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसक आंदोलन करेंगे तो सरकार को उनकी बात को मानना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आगे क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल हम इतना तो कह ही सकते हैं कि देश का माहौल बदल रहा है।यह बदलाव किस रूप में किस सीमा तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

—अतिथि संपादक,

राजेन्द्र भागवत,

(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

संपादकीय

# 80 दिन की आचार संहिता और बदलती चुनावी संस्कृति: राजस्थान ने दिखाई नई राह



अलका सक्सेना

लोकतंत्र में चुनाव जनभागीदारी और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन चुनावों की प्रक्रिया यदि लगातार चलती रहे और उसका प्रभाव महीनों तक शासन-प्रशासन की सामान्य कार्यप्रणाली पर बना रहे तो उसका सीधा असर विकास की गति पर पड़ता है। राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में यह चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय केवल चुनावी प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इस बार स्थानीय लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

किसी भी सरकार के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल सुनने में लंबा लगता है, लेकिन यदि स्थानीय निकाय, पंचायत, विधानसभा और अन्य चुनाव अलग-अलग समय पर लगातार सामने आते रहें तो वास्तविक शासन अवाधि लगातार कम होती जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों तक सरकार और प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। आचार संहिता लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। उसके प्रावधानों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या सरकार को अनुचित लाभ से रोकना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके दौरान नए कार्यों और नीतिगत निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लगती हैं। इसलिए लोकतंत्र की शुचित्ता और प्रशासन की निरंतरता के बीच संतुलन आवश्यक है। राजस्थान में इस बार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न कराने का प्रयास इसी संतुलन की दिशा में दिखाई देता है।

चुनावी प्रक्रिया जितनी समयबद्ध होगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन सामान्य कार्यप्रणाली में लौट सकेगा और निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी अपने दायित्व संपाल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित और कम विखंडित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका व्यापक विचार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की दिशा में चुनावी चक्र को समन्वित करने का है। इसी सोच की राज्य स्तर पर व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

किसी भी सरकार के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल सुनने में लंबा लगता है, लेकिन यदि स्थानीय निकाय, पंचायत, विधानसभा और अन्य चुनाव अलग-अलग समय पर लगातार सामने आते रहें तो वास्तविक शासन अवाधि लगातार कम होती जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों तक सरकार और प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। आचार संहिता लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। उसके प्रावधानों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या सरकार को अनुचित लाभ से रोकना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके दौरान नए कार्यों और नीतिगत निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लगती हैं। इसलिए लोकतंत्र की शुचित्ता और प्रशासन की निरंतरता के बीच संतुलन आवश्यक है। राजस्थान में इस बार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न कराने का प्रयास इसी संतुलन की दिशा में दिखाई देता है।

चुनावी प्रक्रिया जितनी समयबद्ध होगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन सामान्य कार्यप्रणाली में लौट सकेगा और निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी अपने दायित्व संपाल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित और कम विखंडित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका व्यापक विचार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की दिशा में चुनावी चक्र को समन्वित करने का है। इसी सोच की राज्य स्तर पर व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं जैसे अनेक विषय सीधे इन्हीं संस्थाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए इन संस्थाओं का समय पर गठन लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए आवश्यक है। चुनाव जितनी जल्दी पूरे होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संपालेंगे और स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं पर काम शुरू कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। यह व्यापक चुनावी कवायद अपने आप में प्रशासनिक समन्वय की बड़ी परीक्षा है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी है। लंबे समय तक चुनाव चलते रहने से राजनीतिक दलों की ऊर्जा लगातार चुनावी गतिविधियों में लगी रहती है। कार्यकर्ता, संगठन और नेतृत्व लगातार एक चुनाव से दूसरे चुनाव की तैयारी में जुड़े रहते हैं।

यदि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न हो जाते हैं तो राजनीतिक दलों की भी अपना ध्यान व्यापक संगठनात्मक और नीतिगत कार्यों पर लगाने का अवसर मिलेगा। चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। जनता के बीच लगातार उपस्थित रहना, सरकारों के काम का मूल्यांकन करना, संगठन को मजबूत करना और नीतियों पर संवाद करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि किसी भी चुनावी सुधार के सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि चुनाव जितनी जल्दी हुए। असली कसौटी यह होगी कि चुनाव के बाद निर्वाचित संस्थाएं कितनी प्रभावी ढंग से काम करती हैं और सरकार इस अतिरिक्त प्रशासनिक समय का किताना बेहतर उपयोग करती है।

यदि कम अवधि की आचार संहिता के बाद प्रशासनिक णियों में तेजी आती है, विकास परियोजनाओं की गति बढ़ती है और स्थानीय संस्थाएं प्रभावशाली बनती हैं, तो यह प्रयोग निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रशासनिक मॉडल बन सकता है।

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताएं व्यापक हैं। सरकार के पास जितना अधिक निर्बाध कार्यकाल होगा, परिणाम देने की अपेक्षा उतनी ही अधिक होगी।

अंततः यह पहल किसी एक दल की जीत या हार से कहीं बड़ी है। चुनाव आगे और जाएंगे, राजनीतिक दल सत्ता और विपक्ष की भूमिका में आते-जाते रहेंगे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और चुनावी चक्र को अधिक व्यवस्थित बनाना दीर्घकालीन लोकतांत्रिक हित में है। राजस्थान में करीब 80 दिनों के सीमित चुनावी दौर में 3०9 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। पिछली बार लगभग 15 महीने तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया के अनुभव के मुकाबले यह बदलाव बताता है कि चुनावों को शासन की निरंतरता से जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक चुनावी सुधार की सोच और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘एक साथ चुनाव’ के संकल्प के बीच राजस्थान का यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका लक्ष्य अंततः शासन के लिए अधिक निर्बाध समय उपलब्ध कराना है।

लोकतंत्र की ताकत चुनाव से आती है, लेकिन सुशासन की ताकत चुनावों के बीच किए गए काम से तय होती है। यदि राजस्थान चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध करके प्रशासन को अधिक कार्यशील समय दे पाता है, तो यह उस राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हो सकती है जिसमें चुनाव समय पर हों और सरकार का अधिकतम समय जनसेवा और विकास के लिए हो।

—अलका सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क (से।न.)

# माखन बनाम मक्खन

करता तो मां नहीं देती। जानती थी अधिक मात्रा हानि कारक हो सकती है। इस परिदृश्य में फिर भक्त सुदामा कृष्ण के पक्ष में बोल पड़ते हैं “मैया कबहि बड़ेगी छोटी, और मैया में नहीं माखन खायो, मैया ग्वालबाल सब बरवस मुख लिपटायो।” आदि-आदि...

पाठकों को बता दूँ कि यह माखन शायद श्रीकृष्ण के काल से पूर्व भी भारत देश में घर-घर में बनता था और इसी से देसी धी बनाने की विधा पनपी। यह धी आहार के साथ तो खायी ही जाता था इसका एक पड़ा हिस्सा यज्ञ में आहुति देने में प्रयुक्त होता। यह आज भी वैसे ही चलन में है। माखन के निर्माण में दूध कभी उबाला नहीं जाता अपितु बरोसी (चिकनी मिट्टी, कुछ पिली मिट्टी – पोता, को गुथकर एक गहरी थालीनुमा चुलेह का बनाकर धुप में सूखा लिया जाता है। सुखाने पर इसके अंदर गोबर से बनें सूखे उपले जलाकर दूध को एक कुम्हार की बानी हांडी में भरकर गर्म किया जाता है जो कब ही उबलता नहीं अपितु उबलने के ताप से नीचे ही कई घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सिमरिंग कहते हैं। इस क्रिया में दूध के हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दूध के अवयवों से कुछ विशेष तत्व भी पैदा हो जाते हैं। दिन भर सिमर्र किया हुआ दूध ठंडा कर रात को चामन (पूर्वदिवस के देही का एक दो चम्मच) कुछ ठंडी जगह रख दिया जाता है जो भोर तक ही ऐसा करने समय कृष्ण जी बहुधा निकट ही कहीं होते तो मां उस नवीन माखन का एक कौर लल्ला को खिला देती। लल्ला जब और देने की जिह

करता तो मां नहीं देती। जानती थी अधिक मात्रा हानि कारक हो सकती है। इस परिदृश्य में फिर भक्त सुदामा कृष्ण के पक्ष में बोल पड़ते हैं “मैया कबहि बड़ेगी छोटी, और मैया में नहीं माखन खायो, मैया ग्वालबाल सब बरवस मुख लिपटायो।” आदि-आदि...पाठकों को बता दूँ कि यह माखन शायद श्रीकृष्ण के काल से पूर्व भी भारत देश में घर-घर में बनता था और इसी से देसी धी बनाने की विधा पनपी। यह धी आहार के साथ तो खायी ही जाता था इसका एक पड़ा हिस्सा यज्ञ में आहुति देने में प्रयुक्त होता। यह आज भी वैसे ही चलन में है। माखन के निर्माण में दूध कभी उबाला नहीं जाता अपितु बरोसी (चिकनी मिट्टी, कुछ पिली मिट्टी – पोता, को गुथकर एक गहरी थालीनुमा चुलेह का बनाकर धुप में सूखा लिया जाता है। सुखाने पर इसके अंदर गोबर से बनें सूखे उपले जलाकर दूध को एक कुम्हार की बानी हांडी में भरकर गर्म किया जाता है जो कब ही उबलता नहीं अपितु उबलने के ताप से नीचे ही कई घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सिमरिंग कहते हैं। इस क्रिया में दूध के हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दूध के अवयवों से कुछ विशेष तत्व भी पैदा हो जाते हैं। दिन भर सिमर्र किया हुआ दूध ठंडा कर रात को चामन (पूर्वदिवस के देही का एक दो चम्मच) कुछ ठंडी जगह रख दिया जाता है जो भोर तक ही ऐसा करने समय कृष्ण जी बहुधा निकट ही कहीं होते तो मां उस नवीन माखन का एक कौर लल्ला को खिला देती। लल्ला जब और देने की जिह

करता तो मां नहीं देती। जानती थी अधिक मात्रा हानि कारक हो सकती है। इस परिदृश्य में फिर भक्त सुदामा कृष्ण के पक्ष में बोल पड़ते हैं “मैया कबहि बड़ेगी छोटी, और मैया में नहीं माखन खायो

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51

संख्या: 325

प्रभात

कोटा, मंगलवार 8 सितम्बर, 2026

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

## जर्मनी के चुनाव में ‘‘नैशनलिज़्म’’ की पुरजोर ढंग से वापसी ने सभी को चौंका दिया है

अब तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की राजनीति यहूदियों पर हुए अत्याचार से उत्पन्न देशव्यापी ग्लानि पर आधारित रहती थी

–अंजन राॅय–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। क्या इतिहास, यानी किसी समुदाय की सामूहिक याद के तौर पर, आज के चुनाव में कोई भूमिका निभाता है? हां, जर्मनी में पिछले रविवार हुए एक महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है।

एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यानी एएफडी ने देश के एक राज्य में हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत से पूरे यूरोपीय संघ में चिंता की लहर दौड़ गई है और रूस में खुशी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसकी लहरें अटलांटिक पार अमेरिका तक पहुंच गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव के नतीजों का जिक्र किया है।

यूरोप हैरान है और इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या

■ पर, वर्तमान चुनाव में राजनीति का आधार ग्लानि को पीछे छोड़कर जर्मनी के अन्य समृद्ध इतिहास की ओर मुड़ा है।

■ ऐसा लग रहा है, हिटलर की ज्यादातियों की याददाश्त को धूमिल कर जर्मनवासी बिस्मार्क की ओर देख रहे हैं।

■ इस मानसिक बदलाव में, जर्मनीवासी अपने देश को ‘‘एक विचारकों व कवियों’’ के देश के रूप में जानना व याद रखना चाहता हैं।

■ चाहे, आधुनिक जर्मनी, अधिक समृद्ध है। पर, नई पीढ़ी शायद कुछ कम समृद्धि बर्दाश्त करने को तैयार है, पर, अपनी ‘‘जर्मननेस’’ (जर्मन्स) को बरकरार रखने में ज्यादा खुशी महसूस करना चाहती है।

यह जर्मन राष्ट्रवाद के फिर से उभरने की एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है कि नाज़ी दौर के अनुभव के कारण यूरोप अब भी एक तरह की मानसिक बेचैनी

से गुजर रहा हो।

एएफडी ने रविवार को अपने सबसे नए प्रतिद्वंद्वी कंजर्वैटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, यानी सीडीयू

पर जोरदार चुनावी जीत हासिल की है, जो अपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टनर, एसपीडी के साथ गठबंधन में फ़ेडरल लैबल पर शासन करती है।

एएफडी जर्मनी को हिटलर के जर्मनी के बजाय, ओटो फॉन बिस्मार्क के जर्मनी के तौर पर देखने को बढ़ावा दे रही है। वह उन्नीसवीं सदी के जर्मनी और जर्मनी एकता के इतिहास को पढ़ाने की बात कर रही है, जिसमें हिटलर के शासन और राष्ट्रीय समाजवाद, उत्पीड़न और युद्ध की किसी भी गलती को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

बिस्मार्क ने अनेक छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करके उस देश की नौव रखी, जो बाद में बीसवीं सदी में जर्मनी बना। पार्टी ‘‘ज्यादा बिस्मार्क और कम हिटलर’’ की बात कर रही है।

नाज़ी शासन को उसके अत्याचारों से बरी नहीं करते हुए, एएफडी उन लोगों की भावनाओं को सामने रख रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्य निकेतन हादसा, बिल्डिंग की मालकिन, पति व पुत्र गिरफ्तार

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढ हने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संपत्ति की मालकिन उर्मिला गुप्ता (75), उनके पति हरिराम गुप्ता (81) और बेटे महेश

■ हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में 6 युवक थे।

गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद चलाए गए लंबे बचाव अभियान में मलबे के नीचे दबे कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा छात्र थे।

## सरकार को अविलंब आना पड़ा, इसरो के स्टाफ की आशंका दूर करने के लिए

स्टाफ में आशंका का कारण था, ‘‘इन-स्पेस’’ के अध्यक्ष पवन गोयंका का वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘इसरो अब कोई लॉन्च व्हिकल्स’’ नहीं बनाएगा। यह सारा काम अब प्राइवेट सैक्टर व प्राइवेट पार्टियों के लिए छोड़ दिया जाएगा

–डॉ. सतीश मिश्रा–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। मोदी सरकार ने देश की अंतरिक्ष एजेंसी ‘‘इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो)’’ के काम के तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर उसके कर्मचारियों के बढ़ते हुये डर, बेचैनी और चिंता को शुरू में ही खत्म करने की कोशिश की है। कुछ निजी कंपनियों को काम करने के लिए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इसरो से एक बयान

जारी करने को कहा, जिसमें कहा जाए कि इसरो देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था बनी रहेगी। यह कदम इसरो के कर्मचारी संगठनों द्वारा इसरो कुछ गतिविधियों को निजी और सरकारी कंपनियों को सौंपने की योजनाओं पर चिंता जताए जाने के बाद उठाया गया। केन्द्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब विपक्ष मोदी सरकार को संवेदनशील और रणनीतिक तकनीकों को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना का विरोध कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इसरो के कथित निजीकरण को तुरंत

■ पवन गोयंका का इशारा था कि इसरो अब भविष्य में स्पेश रिसर्च व नई-नई टेक्नॉलजी विकसित करने की आर एण्ड डी का ही काम करेगा।

रोकने की मांग की है।

विपक्ष का विरोध ‘‘आईएन-स्पेस’’ के अध्यक्ष पवन गोयनका के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘आखिरकार इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान न तो बनाएगा और न ही उसका निर्माण करेगा’’ और इसका पूरा उत्पादन सरकारी उपक्रमों या निजी कंपनियों को पूरी तरह सौंप

दिया जाएगा।

गोयनका के इस बयान के बाद, इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध पत्र जारी किया। भारत अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है।

इसरो ने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के

पास यान उतारा है और अपना खुद का प्रक्षेपण तंत्र यान विकसित किया है। वह देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की भी तैयारी कर रहा है।

एजेंसी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इसरो उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक के विकास, राष्ट्रीय और रणनीतिक अभियानों, अंतरिक्ष विज्ञान और खोज तथा अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक क्षमताओं के लिए भारत का प्रमुख संस्थान बना रहेगा।

इस पोस्ट में उन आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश की गई कि

संगठन का न तो निजीकरण किया जाएगा और न इसका महत्व ही कम किया जाएगा।

यह बयान 4 सितंबर को कर्मचारी संगठन के उस पत्र के बाद आया, जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया था और ‘‘रॉयटर्स’’ ने भी देखा था। इसमें इसरो के कुछ कर्मचारियों ने इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन से उन खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि वर्तमान में एजेंसी द्वारा संचाली जा रही निर्माण और संचालन की जिम्मेदारियां कंपनियों को सौंप दी जाएंगी।

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया। क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वह पुलिस को अपना आवेदन दे। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी।

छह विधानसभा व एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को

नई दिल्ली, 07 सितंबर। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन छह सीटों पर मतदान छह अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना नौ अक्टूबर को की

■ मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

आयोग के अनुसार, तमिलनाडु की मद्रुरांतकम (अनुसूचित जाति) और धारापुरम (अनुसूचित जाति) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुदुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर भी मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर रिक्तियां संबंधित निर्वाचित सदस्यों के इस्तीफे के कारण हुई हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नौ सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान छह अक्टूबर और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

## राहुल की यात्रा से पूर्व पायलट को पंजाब की खेमेबाजी का समाधान निकालना है

जिम्मेवारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मु.मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, एक बड़े खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं

–जाल खंबाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। पंजाब कांग्रेस में हुए फेरबदल ने पार्टी की प्रदेश इकाई को न केवल हैरान किया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि केन्द्रीय नेतृत्व के पास जानकारी हासिल करने की अपनी निजी व्यवस्था भी है और वह किसी एक व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं है।

कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को पंजाब भेजा था, तथा उन्हें गुटों में बँटी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। अब बघेल को पंजाब से हटा दिया गया है और उनकी जगह सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई है।

पंजाब के नये प्रभारी सचिन

■ साथ ही यह भी विदित है कि राजस्थान के प्रभारी के रूप में रंधावा को गहलौत समर्थक माना जाता है।

पायलट ने राजस्थान में भी इसी तरह की गुटबाजी का सामना किया है और वे अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है।

एक खास दिलचस्प बात यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो इस समय चन्नी खेमे में एक प्रमुख नेता हैं, पायलट के गृह राज्य राजस्थान के प्रभारी हैं।

अब पायलट की जिम्मेदारी होगी कि वे रंधावा को चन्नी खेमे से अलग करके अपने साथ लाएं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब के सभी गुटों में पायलट को स्वीकार किया जाता है और हाईकमान के इस फैसले का पार्टी

नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, दोनों ने स्वागत किया है।

अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पायलट के सामने, राहुल गांधी के पंजाब दौरे से पहले, सभी नेताओं को एकजुट करने की चुनौती है, ताकि एकता का माहौल बनाया जा सके और जनता को यह संदेश दिया जा सके कि अंदरूनी बदलावों के बाद ‘‘सब चंगा सी’’, यानी सब कुछ ठीक है।

फिलहाल एक गुट का नेतृत्व चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं, जबकि विधानसभा में

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग अपने-अपने अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राजा वर्डिंग को जिला अध्यक्षों का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि उन्हीं ने उनकी नियुक्तियां की थी।

प्रभारी के रूप में बघेल से उम्मीद की गई थी कि वे इन गुटों को एक साथ लाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो सके और उन पर आरोप लगा कि वे खुद ही एक अलग गुट बन गए थे।

कांग्रेस हाईकमान को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बघेल ने यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की थी और, खास तौर पर, राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने की बात कही थी।

दिल्ली में संगठन प्रभारी के साथ हुई बैठक में, चन्नी और रंधावा ने वर्डिंग को हटाने की मांग की थी। इस बीच, राहुल गांधी के पंजाब के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पर 14 तक फैसला ले- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया। क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वह पुलिस को अपना आवेदन दे। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी।

CM / K

⊕

⊕

⊕

CM / K



# राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बना : मुख्य सचिव

## 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे : शिखर अग्रवाल

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक ली।

सचिव ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा। उन्होंने निवेश परियोजनाओं से जुड़ी फाइलें शीघ्र प्रस्तुत करने तथा जिला कलक्टरों के साथ समन्वय कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। ऊर्जा एवं राजस्व विभाग से अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने भूमि की पहचान एवं आवंटन से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने को कहा, ताकि निवेश परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश

प्रस्तावों की ग्रांड्ट ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने स्वीकृति योग्य प्रकरणों को शीघ्र मंजूर करने और जिनमें स्वीकृति संभव नहीं है, उनमें तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिए। बैठक में विभागावार लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा की गई तथा निवेश प्रस्तावों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। संबंधित जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े।

■ 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन तक और अधिक एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी के निर्देश दिए

दिवस तक अधिकाधिक एमओयू को धरातल पर उतारने के लक्ष्य के साथ समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। शासन सचिवालय में सोमवार को राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन के दौरान हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्य

## जयपुर, अलवर, सर्वाईमाधोपुर, डीडवाना और कुचामन में जीएसटी विभाग की कार्रवाई

जयपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने कर अप्रवचना, फर्जी बिलिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जयपुर, अलवर, सर्वाईमाधोपुर एवं डीडवाना-कुचामन में किए गए निरीक्षणों में करीब 1.93 करोड़ रुपए की संभावित कर देयता सामने आई, जबकि करदाताओं ने 1.74 करोड़ रुपए से अधिक स्वेच्छिक रूप से जमा या रिवर्स किए। जयपुर की एम/एस पचावती ट्रेवलस एंड कारों के यहां 1 सितम्बर को जांच में 1 करोड़ 38 लाख 88072 रुपए की आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया जाना सामने आया। विभाग की कार्रवाई के बाद करदाता ने पूरी राशि स्वेच्छिक रूप से जमा कर दी। अलवर सॉल्वेक्स के यहां जांच में आग से नष्ट स्टॉक व आईटीसी से जुड़े मामले में करीब 30 लाख रुपए की संभावित देयता

■ निरीक्षण के दौरान 1.74 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स स्वेच्छिक रूप से जमा कराया

सामने आई। यहां एम/एस एडल्यूएल एपी बिजनेस लिमिटेड के लिए सरसों तेल की पैकिंग का जाँचबूक किया जाता है और 11 सितम्बर को दस्तावेज व लेखा पुस्तकों के साथ उपस्थित होने का समन जारी किया गया है। खेरलीवाला प्रोडक्ट्स प्रा. लि., अलवर में करीब 12 लाख रुपए की संभावित देयता के मामले में 10 लाख रुपए जमा कराए गए। सुजानगढ़ के गायत्री स्टोन क्रशर में सर्कुलर ट्रेडिंग, बिना वास्तविक आपूर्ति के बिल, आरसीएम में अंतर और टैन्डओवर छिपाने की आशंका पर करीब 10.15 लाख रुपए की संभावित देयता आंकी गई और बिक्री

संबंधी दस्तावेज जब््त किए गए। सर्वाई माधोपुर के एम/एस शिव ऑयल इंडस्ट्रीज, खंडार में वर्ष 2022-23 की 16,61,504 रुपए और 2023-24 की 12 लाख 37 हजार 80 रुपए, कुल 28.98 लाख रुपए की आईटीसी के उपयोग का मामला सामने आया। इसमें 15 लाख रुपए स्वेच्छिक जमा हुए और विस्तृत जांच जारी है। डीडवाना-कुचामन के मकराना स्थित एम/एस राधे कृष्णा टिम्बर्स में बिना उचित बिलिंग और आईटीसी के जरिए कर देयता कम करने की आशंका पर करीब 12 लाख रुपए की संभावित राशि आंकी गई। करदाता ने 10 लाख रुपए कैश लेजर के माध्यम से जमा किए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में दस्तावेज, लेखा पुस्तकों, रिटर्न और डिजिटल डेटा के आधार पर जांच जारी रहेगी तथा तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

## मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए 9 व 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के तहत मतदान के दिन मतदाता सूची में नाम वाले नियोजित कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि 9 एवं 11 सितंबर में से जिस तारीख को संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा, उस दिन वहां स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी पात्र कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

## 399 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच

जयपुर। जन्माष्टमी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने 1 से 5 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान दूध, मावा, पनीर, घी, मिठाई, मसाले सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों और

## साक्षरता से सशक्त होता है समाज : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि व्यक्ति को ज्ञान, आत्मनिर्भरता, जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

देवनानी ने कहा कि एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज तथा विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है। साक्षरता व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है तथा समाज की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम करती है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा ने सदैव शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया है।

ज्ञान व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के साथ-साथ समाज में विवेक, समानता, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

## राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल ने ली शपथ



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को लोकभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल को शपथ दिलाई।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को लोकभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे संजय के. अग्रवाल को शपथ दिलाई। जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के 44 वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। शपथ के बाद राष्ट्रपति भवन से जारी वारंट पर साइन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्यपाल से जस्टिस संजय के. अग्रवाल को शपथ

दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की ओर से सीजे अग्रवाल के नियुक्ति वारंट को पढ़कर सुनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, हाईकोर्ट के जज, अधिकारी व वकील सहित सीजे अग्रवाल के परिजन भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सीजे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश

शर्मा व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता के बीच में चल रहे विवाद के दौरान पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 4 सितंबर को भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की और राष्ट्रपति भवन से उनके नियुक्ति वारंट जारी किए गए।

## सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर 16 नवंबर तक पालना रिपोर्ट पेश करो : हाईकोर्ट

### प्रताप नगर सेक्टर-5 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम और हाऊसिंग बोर्ड को निर्देश दिए अदालत ने

**-कार्यालय संवाददाता-**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर से नगर निगम और आवासन मंडल को अतिक्रमण हटाकर 16 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विकास समिति सेक्टर 5 की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में प्रमुख नगरीय विकास सचिव सहित जेडीए, निगम और आवासन मंडल के अधिकारी अदालत में पेश हुए। प्रमुख नगरीय विकास सचिव की

ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में गत 3 सितंबर को बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें निर्णय लिया गया की मौके पर मौजूद अतिक्रमणों को आवासन मंडल और नगर निगम मिलकर हटाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तीन माह का समय मांगा गया।

इस पर अदालत ने निगम आयुक्त और आवासन मंडल से 16 नवंबर को शपथ पत्र पेश कर पालना रिपोर्ट दायर करने को कहा है। बीती सुनवाई पर अदालत के सामने आया था कि कॉलोनी को नगर निगम के क्षेत्राधिकार में सौंपा जा चुका है। वहीं निगम आयुक्त

ने अदालत में पेश होकर कहा था कि विवादित कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि जब जवाब पेश कर मौके पर अतिक्रमण माना जा चुका है तो फिर उसे हटाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव, जेडीए और आवासन मंडल सचिव सहित निगम आयुक्त को 7 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास काबरा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2022 को नगर

निगम को आदेश दिए थे कि वह अतिक्रमण के संबंध में मिली शिकायतों का परीक्षण करें और अतिक्रमण पाए जाने पर चार माह में नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके बाद 24 जुलाई को जेडीए और आवासन मंडल सहित अन्य विभागों के अफसरों ने बैठक कर माना की मौके पर करीब 145 अतिक्रमण हैं, लेकिन इन्हें रोड, सीवरेज और बिजली-पानी के कनेक्शन जारी हो चुके हैं। इसलिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर इन्हें नियमित करने की छूट मांगी जाएगी। इस प्रार्थना में भगवान गणपति का विशेष कि है। इसके बावजूद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

# जिंदा बम प्रकरण में उम्रकैद काट रहे अभियुक्त को रिहा करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

## जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मामला

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त मोहम्मद सरवर आजमी को रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसाद बी. पराले की खंडपीठ ने यह आदेश सरवर आजमी की ओर से दायर सजा सस्पेंड के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत

के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता। प्रार्थना पत्र में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि घटना के दिन हुए आठ बम धमाकों में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। इसके अलावा एक बम जिंदा मिला था। वह ब्लास्ट हुए बम धमाकों को लेकर चले आठ मामलों में हाईकोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है। सभी 9 बम एक ही साजिश का हिस्सा थे, इसलिए यदि उसे आठ मामलों में निर्दोष पाया गया है, तो इस जिंदा बम के मामले में उसे जेल में नहीं रिहा जा सकता।

प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उसे मामले में घटना के 12 साल

■ अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता।

बाद गिरफ्तार किया गया और यह करीब पन्द्रह साल जेल में बिता चुका है। इसलिए उसे रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि जिंदा बम का

मामला आठ अन्य मामलों में पूरी तरह अलग है। जिस साइकिल का उपयोग बम ले जाने के लिए किया गया था, उसे बेचने वाले विक्रेता ने सरवर आजमी को बतौर खरीदार के तौर पर पहचाना है। इस साक्ष्य को पहले के मामलों में हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया था। वहीं आठ मामलों में बरी करने के फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एजजी ने कहा कि देरी से गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि मामला फर्जी है। इसलिए आरोपी की सजा को स्थगित नहीं किया जाए। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर

में एक के बाद एक आठ जगह ब्लास्ट हुए थे। वहीं चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था। विशेष अदालत की ओर से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में रद्द कर सरवर आजमी सहित अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। वहीं विशेष अदालत के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिसमें फैसला देते हुए अदालत ने 8 अप्रैल, 2025 को शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सेफुर्हमान और सरवर आजमी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

**-कार्यालय संवाददाता-**

जयपुर। छोटी काशी के प्रसिद्ध मोती ङ्गरी गणेश मंदिर में सोमवार से प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव कार्यक्रमों का आगाज हुआ। जन्मोत्सव के

■ 14 सितंबर को स्वर्ण मुकुट में दर्शन देंगे मोती ङ्गरी गणेशजी



पहले दिन महिलाओं की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं कलश में गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचीं और यह जल प्रथम पूज्य भगवान गणेश को अर्पित किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर गणपति के जयकारों से गुंज उठा।

मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के आसपास रहने वाले विभिन्न समाजों के लोगों ने करीब 11 वर्ष पहले भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए कलश में गंगाजल लाने की अनुमति ली थी। धीरे-धीरे यह पहल कलश यात्रा का रूप लेती गई। अब हर वर्ष महिलाएं कलश

यात्रा के रूप में गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचती हैं और इसे भगवान गणेश को अर्पित करती हैं। कलश यात्रा से लाए गए गंगाजल से भगवान गणेश का स्नान कराया गया।

इसके बाद विधि-विधान से अभिषेक किया गया। भगवान को चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण कराई गई और विशेष शृंगार किया गया। पूजा-

अर्चना के बाद प्रथम पूज्य को मोदकों का भोग लगाया गया। मंगलवार को पुष्प नक्षत्र में भगवान गणपति का विशेष पंचामृत अभिषेक होगा। इसके लिए 251 किलो दूध, 50 किलो दही, 25 किलो बूरा, 11 किलो शहद और 11 किलो घी का इस्तेमाल किया जाएगा। 14 सितंबर को स्वर्ण मुकुट में मोती ङ्गरी गणेशजी के दर्शन होंगे।

## कांग्रेस ने रखा जयपुर के कायाकल्प का खाका

जयपुर। नगर निगम चुनाव को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस ने सोमवार को वर्ष 2027 से 2032 तक के लिए अपना घोषणा पत्र 'जयपुर-2032 परिवर्तन का संकल्प' जारी किया। कांग्रेस ने इसे 'मिशन-25' बताते हुए शहर के विकास से जुड़े 25 प्रमुख मुद्दों पर काम करने का रोडमैप पेश किया। इसमें यातायात, जलभराव, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल, पर्यटन, विरासत, सफाई और नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए हैं।

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने घोषणा पत्र जारी किया। शर्मा ने कहा कि दस्तावेज को तैयार करने में आर्किटेक्ट, वित्तीय विशेषज्ञ और पत्रकारों समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए समय, बजट और परिणाम की निगरानी पर जोर दिया गया है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने

■ वर्ष 2032 तक शहर के हालात बदलने का दावा

2032 तक सभी 150 वार्डों में सिटी सेंटर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 2027 में सर्वे कर स्थान चिह्नित किए जाएंगे। हर वार्ड में वार्ड सभा और वार्ड मित्र बनाए जाने का भी वादा किया गया है। हर साल के कार्यों की योजना पहले से तैयार कर काम शुरू और पूरा करने की समय सीमा तय करने की बात कही गई है। वहीं 2028 तक पूरे शहर का वैज्ञानिक जल निकासी मानचित्र तैयार कर 2032 तक प्रमुख जलभराव वाले क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य है। नलों के सुधार, पुलिस पुनर्निर्माण, भूमिगत जल निकासी, वर्षाजल संचयन और प्राकृतिक जलमार्गों के पुनर्जीवन का प्रस्ताव है। 50 प्रमुख मार्गों और 100 चौराहों को आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने, कैमरे और सेंसर के जरिए जाम की निगरानी की योजना है।

## पीएम सूर्यधर योजना के लिए वैंडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दें : मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पीएम-कुसुम, पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, आरडीएसएस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरणों, राइट ऑफ वे मामलों तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त विद्युत संबंधी शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यधर योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वैंडर्स की क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप के माध्यम से अधिक से अधिक वैंडर्स को प्रशिक्षण देने और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।

## ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की पहल राजस्थान से हुई : मदन राठौड़ प्रदेश की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना चुकी : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। राजस्थान की जनता विकास के लिए 'ट्रिपल इंजन की सरकार' बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय निकायों में भाजपा की सरकार बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा संसाधनों की कमी नहीं रहेगी।

राठौड़ ने कहा कि भाजपा के पास योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है। टिकट नहीं मिलने से कहीं नाराजगी या विरोध है तो उसे बातचीत और संतुष्टन के स्तर पर दूर किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर भी कहा कि देश और राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं को बदनाम करने वालों को



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल के वार्ड 110 में जनसंपर्क किया।

कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल

शर्मा ने राजस्थान में 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की पहल की है। स्थानीय

निकाय, पंचायत और सहकारिता क्षेत्र के चुनाव एक साथ होने से बार-बार

चुनावी प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा और सरकार व जनप्रतिनिधि विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। राठौड़ ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में जयपुर शहर के विधायकों के साथ बैठक कर प्रस्तावित रोड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने वार्ड 110 की भाजपा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, वार्ड 111 के संजय जायसवाल और वार्ड 108 की मीनाक्षी पारीक के समर्थन में जनसंपर्क किया। शाम को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 35 में भाजपा प्रत्याशी विमल कटियार के समर्थन में धावास रोड स्थित यादव मैरिज गार्डन से रजनी विहार, जगदंबा नगर ए, बी, सी, जगदीशपुरी एवं निर्बाक मंदिर क्षेत्र तक रोड शो किया। इसमें विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राजेश्वर सिंह राठौड़ सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देर शाम वार्ड 137 में भाजपा प्रत्याशी विमल अग्रवाल के समर्थन में भी प्रचार किया।

## सार-समाचार

## वरिष्ठ नागरिक संस्थान कोटा ने शिक्षकों का सम्मान किया

कोटा, (निसं)। वरिष्ठ नागरिक संस्थान कोटा द्वारा शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष टी.पी.एस सेठी ने बताया कि आबधिक बैठक के दौरान समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देते हुए संस्था के शिक्षक सदस्यों का विशेष सम्मान किया गया। सम्मानित शिक्षकों महेश चतुर्वेदी, रचना भार्गव, कुसुम हटौला, संगीता कक्कड़, ऊषा गुप्ता, अनीता गुप्ता, अलका शुक्ला, अनुराधा अग्रवाल, संतोष वासुदेव, महेंद्र राठौर, ममता, अशोक शुक्ला आदि में से संगीता कक्कड़ और अलका शुक्ला ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। इस दौरान एकजीक्यूटिव चैयरमैन ब्रिगेडियर एन.एस.कपूर और राम मदनानी ने शिक्षक और शिक्षा के महत्व को अहम बताया। महासचिव डी.के.अरोरा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षकों के स्वागत किया और संस्था की गतिविधियों को जानकारी दी। पूर्व में कार्यक्रम का प्रारंभ सर्व धर्म प्रार्थना और राष्ट्रगान से किया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भजन और नृत्य नाटिका के अतिरिक्त मनोरंजक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रखी गईं। मॉरिंग के प्रारंभ में मेडिकल कैंप रखा गया जिसमें डॉक्टर एस.डी.शर्मा ने निशुल्क परामर्श दिया और इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण जांचे रखी गईं, जिसका सभी ने लाभ उठाया। सेठी ने आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी दी।

## ओ पॉजिटिव एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। टीम जीवनदाता के प्रयासों से निरंतर लोगों की मदद की जा रही है, ऐसे में अब महिलाएं भी सेवा के क्षेत्र में आगे आकर एसडीपी डोनेशन कर रही हैं। लार्यस क्लब कोटा टेकनो के निदेशक व टीम जीवन दाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि नयापुरा निवासी एहसान की प्लेटलेट्स 10 हजार रह गई थी उन्हें डैंगू के चलते चिकित्सकों ने ओ पॉजिटिव एसडीपी के लिए कहा, ऐसे में उनके पिता अंसार अली पूर्व में भी टीम जीवनदाता से मदद ले चुके हैं और सीधा ही अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे, रात्रि कोडोनस की तलाश की गई, ऐसे में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने वाले अतुल विजय से संपर्क किया और उनकी पत्नी हेमा विजय से आग्रह किया, हेमा विजय शीघ्र ही तैयार हो गई और उन्होंने अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचकर दूसरी बार ओ पॉजिटिव एसडीपी डोनेट की दी। वह इससे पूर्व भी ब्लड डोनेशन कर चुकी हैं। हेमा विजय ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो भाग्य खुल गया और अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूं। उन्होंने कहा कि वह इस कार्य में और भी महिलाओं को जोड़कर सेवा का कार्य करेंगी।

## ‘खाद्य सुरक्षा मानक’ विषय पर व्याख्यान आयोजित

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय, कोटा में सोमवार को उपभोक्ता क्लब के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा मानक”विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. प्रप्रिमा श्रीवास्तव ने की उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी के बारे में हमे जागरूक होना है क्योंकि जैसा खानेपान, वैसा होगा हमारा मना। अतः हम भी जागरूक रहे व दूसरों को भी जागरूक करे और अपने विचारों और नवाचार को प्रेषित करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. नीरज श्रीवास्तव ने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के चयन तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया। व्याख्यान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों व फूड पॉजनिंग के दुष्प्रभाव, फूड मानक, भारतीय लोगों में जागरूकता वर्ष 2006, खाद्य पीठासीन व विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। फूड वन डिजीज बीमारी में भारत की स्थिति वर्ष 2006, खाद्य पीठासीन व विद्यार्थी व एफएसएसआई के नियमों, फूड स्तर के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया।

## मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित

छबड़ा (निसं)। चुनाव आयोग एवं शिक्षा विभाग बीकानेर के आदेशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान, मतदान शिक्षा और नगर निकायों के चुनावी माहौल के मद्देनजर सोमवार को हैप्पी चिल्ड्रन सेंकेंडरी स्कूल छबड़ा में बॉयज कैम्पेन और गर्ल कैम्पेन एवं वाइस कैम्पेन के चुनाव कक्वाए गए। जिसमें बच्चों को पहले मतदान के बारे में बताया गया उसकी प्रक्रिया को समझाया गया तथा सही प्रत्याशी को चुनने की सलाह दी गई। विद्यालय व्यवस्थापक कंभर पाटीक के अनुसार विद्यालय में इस चुनाव में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। चुनाव में आठ प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। जिनमें से एक बॉय कैम्पेन और एक गर्ल कैम्पेन को मत पत्रों द्वारा प्रत्येक बच्चे द्वारा दो वोट देकर चुना गया। विद्यालयी चुनाव प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संपन्न करवाने में चुनाव पीठासीन अधिकारी इरफान खान, मीडिया प्रभारी नीरज भार्गव, चुनाव निरीक्षक एकता शर्मा और योगेंद्र सिंह भाटी, मत गणना अधिकारी पवन नामदेव, अमन शर्मा और रजनीश शर्मा का पूर्ण सहयोग रहा। चुनाव में वंश नाना को बॉय कैम्पेन और अलशिफा खान को गर्ल कैम्पेन वहीं विष्णु प्रदाद लोधा को वाइस बॉय कैम्पेन और आरोही शर्मा को वाइस गर्ल कैम्पेन चुना गया।

## महाविद्यालय में 5 किलोमीटर मैराथन प्रतियोगिता आयोजित

छबड़ा (निसं)। अमरचंद राजकुमारी बरडिया जैन विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में 5 किलोमीटर मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर की ओर से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित गतिविधियों के अंतर्गत हुई। रेड रिबन क्लब प्रभारी डॉ. बिश्वोलाल बैरवा ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 से 25 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.सी. मीणा ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता में रवि तेजस्वी (बीए द्वितीय सेमेस्टर) ने 19 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दीपक कश्यप ने 21 मिनट में दूरी पूरी कर द्वितीय तथा विशाल ऐरवाल ने 23 मिनट में दौड़ पूरी कर तृतीय स्थान हासिल किया। समापन पर प्राचार्य डॉ. आरसी मीणा ने प्रतिभागियों को बधाई दी तथा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में सहयोगिता से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है।

## अवैध पिस्टल सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रानपुर पुलिस टीम ने इलाके में गश्त व चौक़िंग के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध देशी पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। रानपुर थानाधिकारी रमेश कविया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निदेश पर अवैध हथियार के तलाश कार्यवाही के लिये अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी ने बताया कि थाने के सहायक उप निरीक्षक रामसिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान चौक़िंग कर रहे थे, चौक़िंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिस पर संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर डिटैन कर तलाशी ली तो तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देशी निर्मित पिस्टल बरामद की गई, पिस्टल के संबंध मे वैध लाईसेंस नही होने पर पुलिस टीम ने मौके पर आर्मस् एक्ट में कार्यवाही करते हुए थाना अंतर्गत के ओम कोठारी निवासी इंदरेश खान (27) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

## अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। अयाना पुलिस टीम ने इलाके में कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करी की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अयाना थानाधिकारी रघुबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके के गण्डावद के समीप चौक़िंग के दौरान एक जने पर संदेह होने पर उसको डिटैन कर तलाशी ली तो तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए थाना अयाना के मीठोद निवासी गिराज (37) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

# नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कोटा ग्रामीण पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला

कोटा, (निसं)। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में कोटा ग्रामीण इलाके के थाना इटावा एवं थाना सुल्तानपुर क्षेत्र में संबंधित वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस जापे के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया।

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च कर आमजन को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देकर उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि कोटा ग्रामीण

## मतदान जागरूकता की शपथ दिलवाई

बूंदी (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी में सोमवार को निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईलसीटी) के अंतर्गत मतदान शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान के अधिकार एवं मतदाता के कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संदीप यादव ने की। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने छात्राओं से स्वयं जागरूक मतदाता बनने तथा अपने परिवार एवं समाज के लोगों को भी निष्पक्ष, निर्भीक एवं शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करने का आब्हान किया। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला जागरूक मतदाता ही होते हैं।

# सेवाभाव के साथ नव्या क्लब ने वृद्धाश्रम में नंदोत्सव मनाया

कोटा, (निसं)। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर नव्या क्लब की ओर से सोमवार को बजरंग नगर स्थित कृष्ण नगर, गली नंबर 1 के अपना घर वृद्ध आश्रम में नंदोत्सव मनाया गया। क्लब की संस्थापक अध्यक्षा आशीता माहेश्वरी ने बताया कि क्लब सदस्यों ने बुजुर्गों के साथ कृष्ण जन्म की खुशियां साझा करते हुए सेवा और अपनत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्याएं पीले रंग की साड़ी में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुईं।

भजन एवं कृष्ण भक्ति के बीच आयोजित नंदोत्सव में वृद्धजनों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पूरे आयोजन के दौरान आश्रम में भक्तिमय और आत्मीय वातावरण बना रहा। इस अवसर पर क्लब की ओर से वृद्धजनों के लिए भोजन सेवा की गई तथा आश्रम के उपयोग के लिए खाद्य सामग्री भेंट की गई। सदस्यों ने बुजुर्गों से संवाद कर उनके अनुभव सुने और उनके साथ समय बिताया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि

त्योहारों की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उनकी खुशियां समाज के उन लोगों तक भी पहुंचें, जिन्हें स्नेह और साथ की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से नंदोत्सव को वृद्ध आश्रम में आयोजित किया गया। श्रीकृष्ण के प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश को आत्मसात करते हुए क्लब भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करता रहेगा। आयोजन के अंत में सदस्यों ने वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया। सेवा, भक्ति और आत्मीयता से सजा यह नंदोत्सव सभी के लिए यादगार रहा। इस अवसर क्लब के पदाधिकारी मंजू लुक्कड़, राजा कचोलिया, रजनी मोदी, पूजा गुप्ता, विनीत शर्मा आकांक्षा सक्सेना नीतू गाँड, अलका बाहेडिया, रीमा लखोटिया, बिना तोशनीवाल, नीलिमा तोगनीवाल, संगीता तोषनीवाल, अंजना शारदा, सारिका सोलिवाल, कल्पना जायसवाल, रश्मि शर्मा, सीमा शर्मा, अनीता गोयल सुधा जैन, लक्ष्मी शर्मा कोमल अग्रवाल, ममता परीक आदी उपस्थित थे।

# सीईओ ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

बूंदी (निसं)।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाओं में प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद स्थित कक्ष में मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारू की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावित, स्वीकृत व प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों की आम समस्याओं जैसे नाली, सड़क, पानी, रमेशन सहित

## ‘ कार्य स्वीकृति में लाएं तेजी, स्वीकृत कार्यों को तत्काल प्रारंभ करवायें

अन्य आवश्यक कार्यों की स्वीकृतियां पंचायतीराज आचार संहिता लगने से पहले नियमानुसार स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारंभ करवाये जावे। सांसद व विधायक कोष के तहत प्रस्तावित कार्य जिन्हें नियमानुसार करवाया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित माननीय लोकसभा व विधानसभा सदस्य को समय पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उन्होंने विक्सित भारत- जीरामजी योजना के संबंध में निर्देश दिए कि पंचायती राज आचार संहिता के दौरान ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को नियमित



नगर निकाय चुनावों को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये ग्रामीण पुलिस अधिकारी व जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला।

पुलिस द्वारा चुनाव को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

# प्लॉट पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने वाले को पकड़ा

कोटा, (निसं)। प्लॉट पर धोखाधड़ी से कब्जा कर निर्माण कराने के दर्ज मामले में कुन्हाडी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को फरियादी ने कुन्हाडी थाने पर रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसका प्लॉट गणपति नगर बूंदी रोड पर है, जिसको उसने 2001 में खरीदा है। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि विमल मिश्रा नाम का व्यक्ति उसके प्लॉट पर अवैध कब्जा कर निर्माण करवा रहा है पुलिस द्वारा की गई समझाईश के बाद भी नहीं मान रहा है। रिपोर्ट में कहा कि जब वह प्लॉट पर गया तो विमल मिश्रा

## तीन वर्ष से फरारी काट रहा था उतरप्रदेश निवासी आरोपी

ने उसकी पत्नी को अपशब्द कहे और मारपीट पर उतार हो गया।

शहर एसपी ने कहा कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया, मामले में कार्रवाई के लिये कुन्हाडी थानाधिकारी देवेश भाद्राज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने मामले मे अनुसंधान करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश दी।

पुलिस को टीम में लगातार उसके

संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं, लेकिन वह बार-बार अपनी पहचान और ठिकाने बदल था।

गठित विशेष टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीन साल से फरार चल रहे आरोपी रंगपुर रोड जेपी कोलोनी हाल ग्राम कटरा इन्द्रकुंवर थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ़ उतरप्रदेश निवासी विमल मिश्रा को गिरफ्तार किया।

मामले में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी विमल मिश्रा ने फरारी के दौरान अपने रिश्तेदारों के पास एवं भेष बदलकर राजस्थान, उत्तरप्रदेश में विभिन्न जगहों पर निवासरत रहा है। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

# मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

बूंदी, (निसं)। जिले में नगरीय निकाय चुनाव के सुचारु संचालन और मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) हरफूल सिंह यादव ने आदेश जारी कर जिले के संबंधित नगरीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार प्रथम चरण में मतदान दिवस 9 सितंबर (बुधवार) को और द्वितीय चरण में मतदान दिवस 11 सितंबर (शुक्रवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेशानुसार प्रथम चरण 9 सितंबर मतदान दिवस को नगर परिषद बूंदी एवं नगर पालिका देई, इन्द्रगढ़ और केशवगयपाटन (संपूर्ण क्षेत्र) में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

इसी प्रकार, द्वितीय चरण के तहत 11 सितंबर को नगर पालिका लाखेरी,

कापरेन, नैनवां और हिण्डोली (संपूर्ण क्षेत्र) में मतदान किया जाएगा, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेशानुसार यदि किसी कारणवश किसी मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति में उस विशिष्ट मतदान क्षेत्र या क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि के दिन भी सार्वजनिक अवकाश मान्य होगा। श्रम विभाग के निर्देशों के तहत, इन निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अपने संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों (जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं) को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारी सीधे संबंधित टिर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकते हैं।

## सार-समाचार चोरी के दो आरोपी पकड़े, यात्री को पर्स बरामद

कोटा, (निसं)। सर्वाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सतर्कता से चोरी के दो आरोपियों को पकड़कर यात्री का पर्स बरामद किया। पर्स में नकदी, चांदी की अंगुठियां और जरूरी दस्तावेज सहित करीब 8 हजार रुपये मूल्य का सामान मिला। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सर्वाईमाधोपुर प्लेटफॉर्म संख्या एक के कोटा छोर पर एक यात्री ने चोरी की आवाज लगाई। इस पर रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान आरक्षक प्रहलाद मीणा, राजकीय रेलवे पुलिस के सहायक उप निरीक्षक कैलाश चंद और आरक्षक सोमेंद्र ने भाग रहे दो व्यक्तियों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस टीम ने पकड़े गये दोनों आरोपियों के कब्जे से महिला का पर्स बरामद किया, जिसमें 3 हजार रुपये नकद, दो चांदी की अंगुठियां, ड्राईविंग लाईसेंस और आधार कार्ड थे। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कोटा निवासी भानु गौतम और गोपाल यादव को गिरफ्तार किया। मामले में जांच में सामने आया कि गाड़ी संख्या 20177 असारवा एक्सप्रेस के सर्वाई माधोपुर स्टेशन पहुंचने पर चोरों ने यह पर्स ट्रेन के एस-4 कोच से चोरी किया था। मामले में अनुसंधान के बाद अहमदाबाद से आगरा की यात्रा कर रहे यात्री उमंग गौतम से संपर्क करने पर उन्होंने पर्स की पहचान अपनी पत्नी भावना गौतम के पर्स के रूप में की। पकड़े गये दोनों आरोपियों के विरुद्ध राजकीय रेलवे पुलिस थाना सर्वाई माधोपुर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण द्वारा की जा रही है।

## सचिन पायलट को जन्मदिन मनाया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को कोटा में पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम एवं युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव शुभम गोचर ने बताया कि सेवा कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद नगर स्थित सेवाधाम आश्रम से हुई, जहां वृद्धजनों के साथ केक काटकर सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया। इस दौरान वृद्धजनों को भोजन करवाया गया तथा उनका आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद एसी वाले गणेश जी के यहां गौसेवा करते हुए गायों को चारा खिलाया गया। इसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए शहर के 11 सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान कार्यक्रमतों ने लगाए गए पौधों की देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर दीपक योगी, भगवान सिंह भाटी, योगेंद्र गुर्जर, रोहित हुण, सक्षम गौतम, लक्की, बंटी मीणा, उमाशंकर, भोजराज सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

## विज्ञान मेले का आयोजन

रामगंजमंडी, (निसं)। महات्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खैराबाद में सोमवार को विद्यालय स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन संपन्न हुआ। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 12वीं तक के नन्हे वैज्ञानिकों ने भाग लेकर अपनी वैज्ञानिक विद्या और नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोशल सेवा के उपप्रधानाचार्य प्रेमचंद निर्मल ने की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्य हुकुमचंद गुप्ता, हेमेन्द्र शर्मा उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मांडप्लस एवं प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन हेतु गठित निदेशक मंडल में शीतल गुप्ता, अनिता अग्रवाल एवं रीना राठौड़ शामिल रहीं। निर्णायक मंडल ने प्रत्येक प्रतिभागी के मांडल का बारीकी से अवलोकन कर उनसे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चर्चा की।विज्ञान मांडल में केले का डीएनए निकालना, 3- डी होलीग्राम, हाइड्रोजन कार, लेमन बैटरी इत्यादि शामिल रहे। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

## 100 विद्यार्थियों को डेंटल किट वितरित

कोटा, (निसं)। बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राउंड इंडिया की केसीआरटी- 358 की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रथकंदरा में 100 विद्यार्थियों को दंत स्वच्छता किट वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष रोहित जैन ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य और मौखिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह पहल इस वर्ष शुरू की गई है। इसे पविष्य में भी निरंतर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से दांतों की सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान का उद्देश्य है। इस अवसर पर संस्था के सचिव टैबलर रमन भाटिया एवं क्यूनिटी सर्विस कन्वीनर टैबलर सिद्धार्थ गौतम मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने संस्था की पहल की सराहना की। दंत स्वच्छता किट पाकर विद्यार्थी उत्साहित नजर आए।

## फिजियोथैरेपी शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक फिटनेस को लेकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर की पहल पर पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रामीण पुलिस लाइन में फिजियोथैरेपी कैप का आयोजन किया गया। फिजियोथैरेपी कैप में पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा नियमित रूप से व्यायाम एवं शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कैप के दौरान फिजियोथैरिपिस्ट द्वारा पुलिसकर्मियों की शारीरिक समस्याओं की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया तथा कमर, गर्दन, कंधे, घुटने एवं मांसपेशियों से संबंधित समस्याओं के उपचार एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पुलिसकर्मियों को फिजियोथैरेपी एक्सरसाइज एवं स्टूचिंग के बारे में भी बताया गया।

क्र. एक 11 विकास/2026/36

दिनांक : 7.9.2026

नाम हस्तांतरण चाहने वावत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 544 राजीव गांधी नगर स्पेशल आवारसी योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 286 दिनांक 17.01.2020 को श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री लल्लुराम के नाम आवंटन किया गया था। श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री लल्लुराम द्वारा उक्त भूखण्ड का जय गुस्तराआम श्री नरेंद्र कुमार यादव पुत्र श्री लाल्लुराम यादव द्वारा जय रजिस्टर्ड विक्रम पत्र दिनांक 04.04. 2023 को श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल लतीफ को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल लतीफ द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तांतरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्तर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 544 राजीव गांधी नगर स्पेशल आवारसी योजना का नाम हस्तांतरण श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल लतीफ के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगरपालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)

क्र.न.पा.का./2026/1552

दिनांक-07.09.2026

सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न प्राप्ी/ प्राथीगण ने आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर नामहस्तांतरण/विभागीय स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग रहा गया है।

| क्र. सं. का नाम | विभा./पति का नाम | आवेदन सं.     | प्लॉट सं. व दिनांक              | साईज वर्गज                                                 | आवेदित स्वल  | वाहा गया प्रयोजन             |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1.              | रामबाबू सोनी     | रामगोपाल सोनी | LSG/KAPREN/ MUT/2026-27/ 199528 | 135/28.11.2006 व नामांतरण पत्र 174399<br>दिनांक 19.03.2026 | 116.17 वर्गज | गांधी चौक कापरेन प्रयोजनार्थ |
| 2.              | रामबाबू सोनी     | रामगोपाल सोनी | LSG/KAPREN/ MUT/2026-27/ 208450 | 148/26.11.2002                                             | 97.75 वर्गज  | गांधी चौक कापरेन प्रयोजनार्थ |

उक्त आवेदन पत्र संख्याओं में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित में मांग कर दस्तावेजों के 07 दिवस में इस कार्यपालन में प्रस्तुत कर दें। बाक मियाद कोई आपत्ति न करने की जायेगी।

अधिसाथी अधिकारी नगर पालिका, कापरेन

प्रस्तुत आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित में मय सुलगत दस्तावेजों के 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

**अधिकाी अधिकारी नगर पालिका, कापरेन**



